अनपारा ताप विद्युत परियोजना को कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति

6728 **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर-प्रदेश में अनपारा ताप विद्युत परियोजना में कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण विद्युत उत्पादन के काम पर प्रतिकूल प्रभाव जारी है ;

(ख) क्या सरकार ने सभी ताप बिजली घरों को कोयले की समय पर और पर्याप्त रूप से आपूर्ति के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कोयला खानों से कोयले की चोरी को रोकने के लिय कोई ठोस कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० (को० इं० लि०) से प्राप्त सूचना के अनुसार अनपारा तापीय विद्युत गृह का कुल कोयला प्रेषण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित 40.40 लाख टन मांग की तुलना में वर्ष 1994-95 में 64.37 लाख टन (अनंतिम) कोयले का प्रेषण किया गया था। चालू वर्ष 1.4.95 से 9.5.1995 के दौरान आपूर्ति 3,70,970 टन संयोजन की तुलना में 7,68,340 रही है। चूंकि कोयले की आपूर्ति मांग/संयोजन की तुलना में अधिक उच्च रही थी, इसलिए कोयले की कमी से उत्पादन के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला कम्पनियां इस स्थिति में है कि वह वैगनों की उपलब्धता तथा कोयला आपूर्ति के एवज में भुगतान सहित समग्र बाधाओं के बावजूद विद्युत गृहों की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकती हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले का प्रेषण का दैनिक आधार पर प्रबोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में प्रत्येक सप्ताह स्थिति की समीक्षा की जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले के संचालन को रेलवे द्वारा अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। सामयिक समीक्षा के आधार पर जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) कोयला खानों से कोयले की उठाईगिरी को रोकने के लिय कोल इण्डिया लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) आसूचना संग्रहण।

(2) 24 घंटे गश्त लगाना।

(3) अपने पट्टाधारी क्षेत्रों में, गैर-काननी खनन स्थलों को, यदि कोई हों, सील करना।

(4) कोयला कम्पनियों तथा सी० एस० आई० एफ०/स्थानीय पुलिस के चौकसी बल द्वारा अचानक जांच/छापे मारना।

(5) रेलवे वे-ब्रिजों तक लद हुए कोयला ट्रकों के साथ हथियार बन्द जवान तैनात करना।

(6) बैगनों से चोरी बहुल क्षेत्रों में रेल की पटरी के साथ-साथ आर० पी०एफ० के साथ संयुक्त रूप में गश्त लगाना।

(7) कोयला बैल्ट के साथ सम्बद्ध सड़कों पर जांच चौकियां स्थापित करना।

Notice for closure of Burmo Coal Mines

6729. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bermo Coal Mines of the Damodar Valley Corporation Limited had earlier been served closure notice by the Director General, Mines Safety;

(b) if so, the date of the notice and circumstances under which the closure notice was served;

(c) whether it is a fact that Government have now permitted them to reopen the mines;

(d) if so, the provisions under which this has been done;

(e) whether it is fact that the coking coal is also being produced in the mine, but it has been declared as non-coking coal and is being burnt in the boilers of DVC thermal power plant, thereby not only contravening the rules of conservation of coal but also depriving the Government of Bihar from higher royalty payable to them; and

(f) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (f) Government in the Ministry of Coal is not aware of the closure notice if any served by Director General of Mines Safety on Burmo coal mines of Damodar Valley Corporation (DVC). According to the available information, Coal Controller issued a notice dated 11-11-94 on Chairman DVC asking the Corporation to stop production and despatch of coal from Bermo mines to their power station. The notice was issued on the ground that DVC had not obtained permission for reopening the mines under clause 14 of Colliery Control Order. Further according to Coal Controller the coal being mined was coking coal and should not have been wasted by burning in the power station.

Chairman DVC approached the Government for a review of Coal Controller's notice representing that the mines was captive to DVC and that the grade of coal of Bermo mine was declared 'E' non-coking coal and that no revision of grade had been made. Government sought detailed comments of Coal Controller on this representation and ordered that no further action in this regard be taken pending further advice from Government.

Percentage of Slurry from washeries of BCCL and CCL

6730. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the percentage of slurry coming out of different washeries of BCCL and CCL of the feed coal during the last three years;

(b) whether this slurry is being sold as metallurgical coal or non-metallurgical coal;

(c) what is the price and rate at which these slurries are being sold, details thereof, washery-wise;

(d) whether it is a fact that huge quantity of slurry is being sold as slurry reject or under any other nomenclature to particular parties only at a lesser rate; and

(e) if so, the details thereof including names of parties, quantity and rate etc?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) As per information received from Coal India Limited